(घ) इन अधिकारियों की सेवा की शर्तें क्या हैं और इन्हें कितने समय के लिये भेजा जा रहा है ?

डिप्टी उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) नेपाल सरकार ने अपनी विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में परामर्श और सहायता देने के लिये भारत सरकार से परामर्शदाता और विशेषज्ञ मांगे हैं किन्तु उसने विभागाधिकारी नहीं मांगे हैं।

(ख) से (घ). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६]

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता कि नेपाल सरकार के निमंत्रण पर भारत के जो विशेषज्ञ वहां भेजे जा रहे हैं उनके निर्वाचन के लिए कोई नियम निश्चित किये गये हैं या विभाग के अधिकारियों की खुशी पर यह निर्भर होता है कि जिनको चाहें भेज दें ?

श्री ब० रा० भगत : विभाग के अधिकारी और कोआर्डिनेशन कमेटी जांच पड़ताल करके इन अधिकारियों को भेजते हैं।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि नेपाल सरकार ने तीस अधिकारियों की मांग की थी। उनमें से केवल ६ अभी तक भेजे जा चुके हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यह देरी क्यों हो रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : ६ तो भेजे जा चुके हैं और ९ चुन लिये गये हैं। वे भेजे जाने वाले हैं। बाकी १५ की मांग अभी आयी है। उस पर हम सोच विचार कर के शीघ्रातिशीघ्र इन अधिकारियों को भी भेज देंगे।

Industrial and Non-industrial Defence Employees

*537. **Shri A. K. Gopalan†:**
Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering the question of removal of discrimination between the service conditions of non-industrial and industrial employees in the civilian defence services; and

(b) if so, the nature of decision taken thereon?

The Deputy Minister of Defence (Shri Raghuramaiah): (a) No.

(b) Does not arise.

Shri A. K. Gopalan: May I know whether this question of removing the discrimination between industrial and non-industrial workers has been there since 1949?

Shri Raghuramaiah: Differences exist between these two categories of employees. Broadly speaking, it is not the policy to remove these differences entirely, because some of them are dependent on the nature of the work that the employees do in each category. The question, of course, of ameliorating certain service conditions in regard to industrial employees is under the consideration of Government.

Shri S. M. Banerjee: May I know whether it is a fact that on 17th May, 1956, the Defence Ministry officials promised before the Prime Minister to settle the question within six months?

Shri Raghuramaiah: I find there have been discussions in respect of some of the items with the representatives of the Defence Employees Federation, but I am not aware of any specific promise given. I shall look into it.